श्री सभापति: लालू जी, ये कह रहे हैं कि सरकार विचार करेगी।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होना चाहिए।

श्री सभापति: आपने इसे अपनी स्टेट में लागू कर दिया है क्या?

श्री लालू प्रसाद: हम देश से अलग नहीं हैं न।

श्री सभापति: नैक्सट क्वेशन। क्वेश्चन नं० 242.

Establistment of Fluoride Mitigation Centre in Gujarat

*242. DR. A. K. PATEL:†
PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat has submitted a proposal to the Ministry of Rural Development for establishing a Fluoride Mitigation Centre;

(b) if so, whether any decision has been taken thereon; and

(c) if not, by when the decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. In June 2002, Chief Minister, Gujarat had submitted a note to Prime Minister raising the issue of setting up a Fluoride Mitigation Centre in Gujarat. The Government of India was already considering setting up of such a Centre on the basis of recommendations of a Central Task Force for Flurosis Mitigation constituted in 2000 for purposes of evolving appropriate strategy for tackling the problem in a time the bound manner. All India Institute of Hygiene and Public Health (AIIHPH), Kolkata was selected for preparation of a Project Document for establishment of Centre of Excellence for Fluoride Mitigation. AIIHPH had submitted a draft Project Document for setting up of a Fluoride Mitigation Centre in June 2002. The

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. A.K. Patel.

comments of sector experts were invited on the subject. The comments have been received from the experts and a policy decision in this matter is to be taken by the Department of Drinking Water Supply after internal discussions about the feasibility of establishment of such a centre in the country.

(c) No definite time can be indicated for taking decision in the subject.

DR. A.K. PATEL: Mr. Chairman, Sir, Flurosis is a known disease in some parts of Gujarat, particularly in north Gujarat and Amreli district of Saurashtra. It occurs as a result of drinking water containing fluoride. More than 370 villages have been identified in my district only. The Government of Gujarat has submitted a proposal for considering and establishing a Fluoride Mitigation Centre. I would like to know from the hon. Minister what steps he is going to take.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, so far as the establishment of Fluoride Mitigation Centre in Gujarat is concerned, the proposal is under consideration. In this regard, All India Institute of Hygiene and Public Health has submitted a draft report to the Ministry, which we are examining. I think, the final Report of the AIIHPH will be submitted by the end of September. After getting this report, the Government will definitely take a decision so far as setting up of the Fluoride Mitigation Centre in the State of Gujarat is concerned.

DR. A.K. PATEL: The hon. Minister in his reply to part (b) has stated that there would be a time-bound programme for solving this problem. And, in his reply to part (c), he has stated that no definite time can be indicated for taking decision on the subject. I would like to know from the hon. Minister when would this be solved?

SHRI KASHIRAM RANA: The Government wants to establish the centre as early as possible. Now, it depends upon the final report of the All India Institute of Hygiene and Public Health, and I assure the hon. Member that a decision will be taken as early as possible.

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाइए। यह समस्या केवल गुजरात की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है।

श्री काशीराम राणा: राजस्थान में भी है।

श्री सभापति: केवल राजस्थान में नहीं है, और जगह भी है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, गुजरात में और गांधीनगर में Fluoride Mitigation Centre सहित गुजरात के 20 पैंडिंग इश्यूज़ को लेकर हम गुजरात के MPs प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते थे। समय न देने पर हमने उनको कल एक मैमोरेंडम भी दिया है। मैं खास तौर पर नॉर्थ गुजरात की बात करना चाहती हूं और जहां से मैं आती हूं मेहसाना से, वहां पीने के पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि हमें 800 फीट नीचे से पानी मिलता है जिसमें Fluoride बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने सन 2000 से कोलकाता के All India Institute of Hygiene and Public Health ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: वह उन्होंने बता दिया है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: महोदय, मैं वही बात कहना चाहती हूं।

श्री सभापति: वह बात मत कहिए जो आ चुकी है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: वह बात आ चुकी है। वह बात सन 2000 से चल रही है और आज 2003 है, अभी भी वह नहीं हो सका है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को मंगाएगी? यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी पीने के पानी की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की बात कही थी, वह भी अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री सभापति: इस क्वेश्चन में नर्मदा नहीं आ रही है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: महोदय, पीने के पानी की समस्या तो आ रही है, वह इसमें ली जाएगी या नहीं?

श्री सभापति: वह आ रही है। वे जवाब दे देंगे।

श्री काशीराम राणा: सभापति जी, माननीय सदस्या की बात सही है कि गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर पानी का ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा रहा है और उसमें Fluoride की मात्रा बहुत अधिक है। अभी जो कन्फर्म न्यूज है, गुजरात में 1999 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक 1175 गांव ऐसे हैं जहां Fluoride का असर है। जहां तक राजस्थान का सवाल है।...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: राजस्थान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप गुजरात का ही सेटल कर दीजिए।

श्री काशीराम राणा: मैं दो-तीन राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं जिससे उसकी सीरियसनेस पता चले।

श्री सभापति: अगर आप गुजरात का सेटल कर देंगे तो सब हो जाएगा।

श्री काशीराम राणा: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि सितंबर में इसकी फाईनल रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार इसे जल्दी सेट-अप करने के बारे में बहुत ही सीरियस है। मैं यह कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही जल्दी हम यह सेंटर establish कर देंगे।

श्री राजू परमार: सभापति महोदय, जैसाकि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि Central Task Force for Fluoride Mitigation का सन् 2000 में गठन किया गया था, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी जून, 2000 में इसके बारे में मैमोरेंडम दिया है। इन सबकी रिपोर्ट आने के बाद भी आपके रिप्लाई में यह लिखा है कि "No definite time can be indicated for taking decision in the subject." आपका जवाब तो यही है। इसको तुरंत करना चाहिए। आपने डेफिनेट टाइम तो बताया ही नहीं।

श्री काशीराम राणा: सभापति जी, मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक ही यह सेंटर सेट-अप होगा लेकिन मैं कहूंगा कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने तीन बार हमें लिखा है और कल भी उनकी एक चिट्ठी आई है। गुजरात सरकार इसके बारे में बहुत चिंतित है और मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम All India Institute of Hygiene and Public Health को रिपोर्ट जल्दी भेजने के लिए कहेंगे और फिर सरकार immediately उस पर डिसीजन ले लेगी।

Utilisation of funds under the Indira Awas Yojana

*243. SHRI VIJAY J. DARDA:†
SHRIMATI N.P. DURGA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the States/UTs are not sending their monthly progress reports on the implementation of Indira Awas Yojana;

(b) if so, in what manner Government would propose to ensure that the funds allotted to the States under this category are being utilised and are not being reappropriated for other purposes; and

(c) the quantum of funds allotted State/UT-wise and the extent to which the same have been utilised?

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Vijay J. Darda.